न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) : कृषि में आर्थिक स्थिरता का स्तंभ

डॉ शिवचरण मीणा, अनुसंधान अधिकारी, निति आयोग

शारांश: "किसानों के कल्याण के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी योजनाओं को लागू करती है ताकि उनकी उपज को उचित मूल्य मिल सके और आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। 2025-26 के लिए घोषित एमएसपी में वृद्धि, विशेष रूप से गेहूं, सरसों, और चना जैसी फसलों के लिए, कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने का प्रयास है। सरसों और चना जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाने से न केवल खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि दालों और खाद्य तेलों की आयात निर्भरता भी कम होगी। यह मूल्य वृद्धि टिकाऊ कृषि और जलवायु अनुकूल फसल विकल्पों को प्रोत्साहन देती है, जिससे जल और मृदा स्वास्थ्य जैसे संसाधनों का संरक्षण होगा। हालांकि, यह कदम तभी प्रभावी होगा जब इसे व्यापक रणनीति के तहत लागू किया जाए, जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिरता, प्रतिस्पर्धा और पर्यावरणीय चुनौतियों का संतुलन शामिल हो।

"देश में किसानों के कल्याण के लिए सरकार कई योजनाएं और नीतियां लागू करती है, जिनमें **न्यूनतम समर्थन मूल्य** महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के भय से भी राहत मिल सके।

एमएसपी प्रणाली लंबे समय से देश की कृषि नीति का आधार रही है, जिसका उद्देश्य उत्पादन को स्थिर करते हुए किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। सरकार हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, जिससे गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। एमएसपी के माध्यम से किसानों को उनकी लागत से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जाता है, जिससे खेती लाभदायक बनी रहे। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से मंत्रणा के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंज़ूरी देना भारत के कृषि क्षेत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आगामी 2025-26 विपणन सत्र के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी को ₹150 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹2,425 कर दिया गया है, जबकि सरसों और चना की एमएसपी में क्रमशः ₹300 और ₹210 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है इनके अलावा कुसुम और जौ के लिए भी क्रमश: 140 रुपये प्रति क्विंटल और 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने, उनकी आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ खाद्य तेल और दालों की आवश्यक आपूर्ति को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विपणन सत्र २०२५-२६ के लिए सभी रबी फसलों के नुनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)

स. क्र.	फसल का नाम	एमएसपी आरएमएस २०२५-२६	उत्पादन लगत आरएमएस २०२५-२६	लागत पर अंतर (मार्जिन प्रतिशत में)	एमएसपी आरएमएस २०२४-२५	एमएसपी में वृद्धि
1	गेंहूँ	2425	1182	105	2275	150
2	जौ	1980	1239	60	1850	130
3	चना	5650	3527	60	5440	210
4	मसूर	6700	3537	89	6425	275
5	सरसों	5950	3011	98	5650	300
6	कुसुम	5940	3960	50	5800	140

स्रोत: पिआइबी नोट १६ ओक्टोबर २०२४

देश में कृषि को अधिक टिकाऊ एवं पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु इस तरह के नवोन्वेषीय प्रयासों एवं नीतियों की आवश्यकता है। रबी फसलों विशेषकर सरसों और चना के लिए एमएसपी में विशेष वृद्धि देश की व्यापक खाद्य सुरक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। सरसों, रबी मौसम की एक प्रमुख तिलहन फसल है, जो खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि चना भारत भर में सबसे अधिक उपभोग की जाने वाली दालों में से एक है। हालाँकि, इन फसलों का रकबा विगत वर्षों में कम हुआ था, इस रणनीतिक एमएसपी वृद्धि से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में सरसों और चना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक किसानों को इन फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

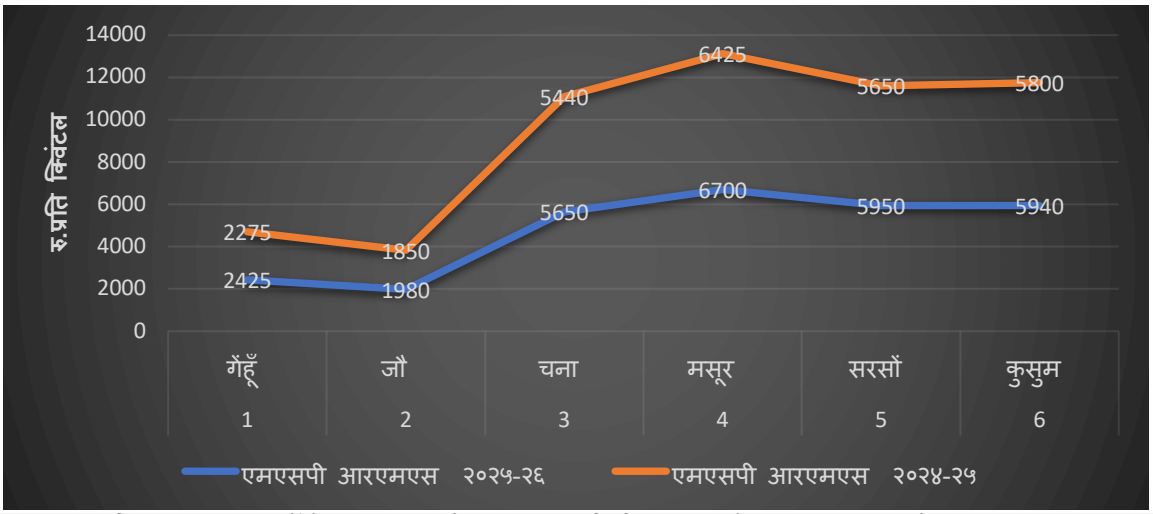

चित्र:१. रबी फसलों के नुनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल) वर्ष २०२५-२६ एवं वर्ष २०२४-२५

खाद्य पदार्थों की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव को देखते हुए, दालों और तिलहनों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर कर देश में इनकी कीमतों को स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।

सतत या टिकाऊ कृषि के दृष्टिगत, सरसों के लिए एमएसपी में हुई वृद्धि एक तरह से फसल विविधीकरण के लिए किये जाने वाले प्रयासों की घोतक है। गेहूं या धान जैसी फसलों की तुलना में सरसों में पानी की कम खपत होने के कारण, अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए अधिक टिकाऊ विकल्प माना जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता तेजी से प्रभावित हो रही है, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना अधिक लचीली कृषि प्रणालियों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में, चने के लिए नवीनतम एमएसपी ₹5,650 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बनाए रखने में अपनी दोहरी भूमिका के लिए सरकार की मंशा का संकेत है। चना, एक दलहनी फसल के रूप में नाइट्रोजन स्थरीकरण करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाये रखने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा में भी महती भूमिका अदा करता है।

निष्कर्ष

रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि सरकार की कृषि को लाभकारी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, लेकिन यह कदम तभी प्रभावी होगा जब इसे एक व्यापक रणनीति के तहत लागु किया जाये| इस रणनीति में किसानों की आर्थिक स्थिरता, वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता एवं पर्यावर्णीय चुनोतियों को संतुलित रूप से सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

जैसे-जैसे वैश्विक खाद्य बाजार विकसित हो रहे हैं और भारत का कृषि क्षेत्र नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, घरेलू किसान कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में हमें संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देना होगा जो खेती की लागत घटाएं, जल प्रबंधन में सुधार करें और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित करें, साथ ही उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है।